an>

Title: Need to take steps to curb infiltration into the country from India-Bangladesh border.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान भारत-बांग्लादेश सीमा पर हो रही निरंतर घुसपैठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यू.एन.ओ. की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार असम के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई जो बांग्लादेश सीमा के आस-पास है तथा बांग्लादेश के उन जिलों में जनसंख्या में असाधारण कमी आई जो भारत सीमा के आस-पास हैं। इसी रिपोर्ट में 1971 से 1981 तथा 1981 से 1991 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करते हुए बांग्लादेश में अचानक एक करोड़ व्यक्तियों के गायब होने की चिंता व्यक्त की गई।

बांग्लादेश घुसपैठ का सबसे घातक प्रभाव असम राज्य में हुआ। इसके साथ-साथ असम के 23 जिलों में से 8 जिलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है। राजनैतिक दृष्टि से नजर डालें तो 126 विधान सभा सीटों में से 46 पर घुसपैठी मतदाता के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू अप्रैल, 2006 में असम के विधान सभा चुनाव में दिखाई दिया जिसमें ब्रह्मपुत्र व कछार घाटी में पड़ने वाले जिलों की जनसंख्या में बड़े नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई व धुबड़ी, गोलपाड़ा और दरंग में तो घुसपैठ के कारण मात्र एक वर्ष में मतदाताओं की संख्या 14 से 15 प्रतिशत बढ़ गई। असम संधि के अनुसार 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आये लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत किये जाने का वक्त दिया गया था जबकि वर्ष 1971 के बाद सीमा पार कर आये प्रवासियों का भारत में रहना अवैध तय किया गया था। असम सरकार ने श्वेत-पत्र जारी करके कहा था कि 1985 से 2012 के बीच विभिन्न न्यायालयों में 61,774 लोगों को अवैध करार दिया गया। यह तो केवल वह मामले थे जो पंजीकृत हुए।

असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा संवेदनशील है। वहां मुर्शिदाबाद जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कथित बांग्लादेशियों और मूल नागरिकों का रहन सहन और भाषा एक है जिसके चलते उनकी पहचान करना मुश्किल है।

भारत में बस गये ऐसे करोड़ों से अधिक घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा तथा अर्थव्यवस्था के लिए बोझ हैं। इनके खाने-पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम खर्च रोजाना 25 रूपये प्रति व्यक्ति भी लगाया जाए तो यह राशि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर होगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है जहां से बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हैं जिसमें पिछले दो दशकों से कटीले तार लगाने का कार्य चल रहा है जो अभी तक 3,300 किलोमीटर तक ही पूरा हुआ है। 2012-13 और 2013-14 के बजट में यूपीए सरकर ने इस कार्य के लिए 100-100 करोड़ रूपये दिये थे। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने इसके लिए अब की बार 500 करोड़ रूपये प्रदान किये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लेने की कृपा करें ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके जिसके वे अधिकारी हैं।